



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 579]  
No. 579]नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 29, 2008/वैशाख 9, 1930  
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 29, 2008/VAISAKHA 9, 1930श्रम मंत्रालय  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2008

का. आ. 1036(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि ईंधन गैसों (कोयला गैस, प्राकृतिक गैस और ऐसी अन्य) के प्रसंस्करण एवं उत्पादन में लगे उद्योग में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 29 के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उप-खंड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2003-आई.आर. (पी.एल.)]

एस. कृष्णन, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT  
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2008

S.O. 1036(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the service in the industry engaged in the ‘Processing or Production of Fuel Gases (Coal Gas, Natural Gas and the like)’ as Public Utility Service for which is covered by item 29 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby declares with immediate effect the said industry to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/2/2003-IR(PL)]

S. KRISHNAN, Addl. Secy.